

‘इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनगि सेरेमनी’: राज्य सरकार और नविशकों के बीच 69,789 करोड़ रुपए के एमओयू

चर्चा में क्यों?

24 अगस्त, 2022 को ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022’ के तहत नई दिल्ली में आयोजित ‘इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनगि सेरेमनी’ में राजस्थान सरकार और नविशकों के बीच 69,789.93 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। इससे राज्य में कुल 11846 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

प्रमुख बंदि

- गौरतलब है कि जयपुर में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022’ के तहत नई दिल्ली में ‘इन्वेस्टर्स मीट एंड एमओयू साइनगि सेरेमनी’ आयोजित की गई। इस एमओयू सहति अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू एवं एलओआई हो चुके हैं।
- 69,789.93 करोड़ रुपए के एमओयू में अवड्डा पावर द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए, ओ2 पावर एसजी पीटीई द्वारा अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए, असाही इंडिया ग्लास लमिटिड द्वारा 1400 करोड़ रुपए, सेंट गोबेन द्वारा 1000 करोड़ रुपए के नविश से फ्लोट ग्लास मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव हैं।
- इसके अलावा वरुण बेवरेजेज लमिटिड द्वारा 636 करोड़ रुपए की कार्बोनेटेड सॉफ्ट-ड्रिंक्स, फ्रूट-जूस एवं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की मैनुफैक्चरिंग यूनिट स्थापति की जाएगी। वपिरो जयपुर में हाइड्रोलिक सिलिंडर प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए का नविश करेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर अपार संभावनाएँ हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिये कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इससे नविशकों को राज्य में नविश करने में आसानी हुई है।
- वर्तमान में रफाइनिरी, पेट्रोकेमिकल्स, सौर ऊर्जा, शक्ति, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भारी नविश करने वाले राज्य के रूप में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान नविशकों के लिये उपलब्ध अनुकूल नीतित्त ढाँचे से पहली पसंद बना है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रीको द्वारा राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापति किये जा रहे हैं। एनसीआर का 25 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में होने से देशभर से बेहतर कनेक्टिविटी है। राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इससे नविशकों को बड़ा फायदा मल्लिगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रपिस के तहत नविशकों को उनकी जरूरत के अनुसार पैकेज दिये जा रहे हैं। एमएसएमई-2019 के तहत नवीन उद्यम इकाइयों को 3 साल तक किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के साथ वन स्टॉप शॉप प्रणाली से सभी सरकारी स्वीकृतियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एमएसएमई एवं रपिस सहति प्रत्येक सेक्टर के लिये पॉलिसी बनाई गई है। जोधपुर ज़िले में 14 हजार एकड़ में फैला वशिव का सबसे बड़ा सोलर पार्क है।
- इस अवसर पर उद्योग एवं वाणजिय मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि डीएफसी कॉरिडोर एरिया का 40 प्रतिशत और डीएमआईसी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य से गुजरता है। सबसे बड़े राज्य और स्ट्रेटेजिक स्थितिके चलते राजस्थान नविश की वशाल संभावनाएँ प्रदान करता है। नविश को बढ़ावा देने के लिये हाल ही में वन स्टॉप शॉप, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, फैसलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।
- राजस्थान लघु उद्योग निगम लमिटिड के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि नविश के लिये राजस्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान बन गया है। राजस्थान को अवसरों की भूमा कहा जाता है। राजस्थान में एक ही पोर्टल पर नविशकों को वभिन्न अनुमोदन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार जयपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिये नवीन फैसलिटि और उद्यपुर में नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, बीकानेर में आईसीडी के साथ राजस्थान के विकास की दशा में कार्य करने के लिये प्रतबिद्ध है।